



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112]	नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2011/फाल्गुन 16, 1932
No. 112]	NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2011/PHALGUNA 16, 1932

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2011

सा.का.नि. 189(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 6 के साथ पठित धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2007 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2007 में, नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“12. आवास—अध्यक्ष और सदस्य साधारण पूल आवासिक आवास के आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगे किन्तु वे उन दरों पर गृह किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो समतुल्य वेतन वाले केन्द्रीय सरकार के अन्य अधिकारियों को अनुज्ञेय है :

परन्तु यदि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति पहले से ही सरकारी आवासन का अधिभोगी है, जिसके लिए समतुल्य वेतनमान के केन्द्रीय सरकार के अधिकारी पात्र हैं, तो वह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण में अपने पद ग्रहण की तारीख से ऐसे आवास को रखने के लिए अनुज्ञात होगा।”

[सं. 2/2011/फा. सं. डी. 11014/1/2010-एसओ(ईएस सेल)]

एस. आर. मीणा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 520(अ), तारीख 1 अगस्त, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्व संशोधन सं.सा.का.नि.199(अ), तारीख 20 मार्च, 2008 और सं. सा.का.नि. 374(अ), तारीख 1 जून, 2009 द्वारा किए गए।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th March, 2011

**G.S.R. 189(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 73 read with Section 6 of the Prevention of Money laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Prevention of Money-Laundering (Appointment and Conditions of Service of Chairperson and Members of Adjudicating Authority) Rules, 2007, namely :—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-Laundering (Appointment and Conditions of Service of Chairperson and Members of Adjudicating Authority) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-Laundering (Appointment and Conditions of Service of Chairperson and Members of Adjudicating Authority) Rules, 2007, for rule 12, the following rule shall be inserted, namely :—

“12. Accommodation.—The Chairperson and Members shall not be eligible for allotment of General Pool residential accommodation but they shall be entitled to draw House Rent Allowance at the rates as are admissible to the other Central Government officers of equivalent pay :

Provided that if the persons appointed as Chairperson or Member is already in occupation of Government accommodation for which Central Government officers of equivalent pay are eligible, he shall be allowed to retain such accommodation from the date of this joining the Adjudicating Authority.”

[No. 2/2011/F. No. D. 11014/1/2010-SO (ES Cell)]

S. R. MEENA, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* No. Notification . G. S. R. 520(E), dated the 1st August, 2007 and amended *vide* No. Notification G.S.R. 199(F), dated the 20th March, 2008 and No. G .S .R. 374(E), dated the 1st June, 2009.